मोहिंदर शर्मा और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

(न्यायाधीश जे. वी. गुप्ता**)**

उक्त नियमों में से 'ए', जन्म तिथि में इस तरह के सुधार को सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर ही लागू किया जा सकता है और जैसे -जैसे यह अवधि समाप्त हो गई है, की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है वादी का जन्म। इसका जवाब पंजाब बनाम किशन चंद (1) राज्य में इस न्यायालय के फैसले द्वारा प्रदान किया गया है, जहां यह आयोजित किया गया था कि यह नियम सिविल कोर्ट से जन्म की तारीख को सुधारने के लिए कोई बार नहीं था। दो साल की अवधि समाप्त हो गई थी। संदर्भ भी श्री मनक चंद वैद्या बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (अन्य (2) के लिए किया गया था, जहां यह आयोजित किया गया था कि एक प्रावधान निर्धारित किया गया था- जब जन्म की तारीख के सुधार के लिए आवेदन का मनोरंजन किया जाना चाहिए, तो उन्हें सीमित करने का प्रभाव पड़ता है। सरकारी नौकर के अधिकार का अभ्यास यह दिखाने के लिए कि रिकॉर्ड की गई प्रविष्टि गलत है। इस तरह की सीमाएं, यह कहा गया था, केवल कानून के बल वाले प्रावधान द्वारा लगाया जा सकता है।

(४) इस तरह कानून में बसे हुए पद के रूप में, कोई अपवाद निर्णय के लिए नहीं लिया जा सकता है और निचली अपीलीय अदालत के निर्णय को वादी को राहत देने वाले वादी को अनुदान दिया जा सकता है। यह अपील शंकु है-quently इसके द्वारा खारिज कर दिया गया है। हालांकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

प्राइसेशन

जे। वी। गुप्ता, जे। मोहिंदर शर्मा और अन्य से पहले

बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य, -सोन्स सिविल रिट याचिका नंबर 5968 1986

26 मई, 1988।

यह माना जाता है कि सरकार ने एक पॉलिसी-सायन लिया है, जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत नोटिफ़ि-केशन के जारी होने के समय मौजूद सभी निर्मित क्षेत्रों को अधिग्रहण से छोड़ दिया गया है। हालांकि, वापसी के अनुसार याचिकाकर्ताओं के पास अधिनियम की धारा 4 के तहत

अधिसूचना जारी करने की तारीख पर विवाद में भूमि पर कोई घर नहीं था। हालांकि यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न हो सकता है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले प्राप्त भूमि पर एक निर्माण उठाया था। जिस अधिसूचना के द्वारा पेटी-टियोनर की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और जिस पर वे पहले से ही अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले निर्माण उठाए हैं, उस सीमा तक खड़ी है।

(पारस 6 और 9)

हेल्ड, कि अदालत में दायर किए गए हलफनामे से यह स्पष्ट है कि उक्त राशि को आर.डी. में या जिला न्यायाधीश के साथ जमा नहीं किया गया था। ऐसा होने के नाते, यह पुरस्कार याचिकाकर्ताओं के संबंध में एक वैध पुरस्कार नहीं था। अधिनियम की धारा 11-ए ने आगे कहा कि धारा 11 के तहत पुरस्कार दो साल के भीतर धारा 6 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से किया जाना है और यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो अधिग्रहण के लिए पूरी कार्यवाही भूमि को समाप्त कर देगा।

(पारस 7 और 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका प्रार्थना करते हुए कि:-

(ए) मामले के रिकॉर्ड के लिए बुलाया जा सकता है;

(बी) प्रबल नोटिफिकेशन एनेक्सर्स पी -1 और पी -2 को जारी किए गए सर्टिफिकेट का एक रिट जारी किया जाना;

(c) उत्तरदाताओं पर अग्रिम नोटिस जारी करने की स्थिति

कृपया के साथ भेजा जा सकता है;

(घ) कोई अन्य उपयुक्त रिट, ऑर्डर या दिशा जो यह माननीय अदालत परिस्थितियों में फिट हो सकती है और इस मामले के तथ्यों पर उचित हो सकती है। जारी किए गए;

(ई) इस माननीय अदालत में वर्तमान रिट याचिका की पेंडेंसी के दौरान, विवाद में भूमि से याचिकाकर्ताओं का प्रसार करना कृपया रुक सकता है;

(च) इस माननीय अदालत में रिट याचिका की पेंडेंसी के दौरान, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के रहने से पहले आगे की कार्यवाही; या कोई अन्य अधिकारी भी विनम्र हो सकते हैं।

यह आगे प्रार्थना की जाती है कि:-

(छ) वर्तमान रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी जा सकती है।

सी। बी। गोएल, अधिवक्ता, संजीव शर्मा के साथ, अधिवक्ता, के लिए याचिकाकर्ता।

राज्य के लिए Pardeep Gupta, अधिवक्ता।

प्रलय

(1) यह आदेश 1986 के 5894 से 5896 से सिविल रिट याचिकाओं का निपटान करेगा, क्योंकि इसमें शामिल सवाल इन सभी मामलों में आम है।

(२) याचिकाकर्ताओं की भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा ४ के तहत अधिसूचना द्वारा अधिग्रहित किया गया था, (इसके बाद एक्ट कहा गया था), १ the नवंबर, १ ९, २ को दिनांकित और अधिनियम की धारा ६ के तहत अधिसूचना १० दिसंबर, १ ९, ४ को अधिसूचना। यह पुरस्कार 21 सितंबर, 1986 को दिया गया था। इस अदालत में अक्टूबर, 1986 में याचिका दायर की गई थी। 1986 के सिविल रिट याचिका नंबर 5968 में कहा गया है कि सितंबर को इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी 21, 1986, जब अधिकारियों के साथ भूमि के मालिकों को भुगतान करने के लिए कोई धनराशि नहीं थी। रिट याचिका के पैराग्राफ 13 में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं की कृषि भूमि के अन्य विखंडन को भी एक और अधिसूचना के तहत अधिग्रहित किया गया था, जिसके बारे में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी यानी 21 सितंबर, 1986 को और याचिकाकर्ताओं और अन्य लोगों ने संपर्क किया। उक्त कृषि भूमि के संबंध में विरोध के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए अधिकारियों। हालांकि, चूंकि अधिकारियों के साथ कोई पैसा नहीं था, इसलिए कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है और न ही ट्रेजरी में जमा की गई राशि, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है। यह भी औसत रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1978 में अधिग्रहित भूमि पर पुक घरों को उठाया था और यह कि उनके संबंधित परिवारों के साथ याचिकाकर्ता उन घरों में रह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संपूर्ण अधिग्रहण अधिकारियों की ओर से भेदभावपूर्ण है, जैसा कि इसी तरह से स्थित व्यक्तियों के घरों और भूमि को अधिग्रहण से बाहर छोड़ दिया गया है, जबकि जिस भूमि पर याचिकाकर्ताओं द्वारा घरों का निर्माण किया गया है, उसे अधिग्रहण किया गया है। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर की ओर से दायर लिखित बयान में, यह एक प्रारंभिक आपत्ति के रूप में कहा गया है कि

कब्जे को पहले ही लिया जा चुका है और इसलिए, राज्य सरकार में भूमि निहित हो गई है और यह कि रिट याचिका को अकेले इस मैदान पर खारिज कर दिया गया था। जैसा कि घरों के निर्माण के संबंध में है, यह रिटर्न के पैराग्राफ 2 में दिनांकित किया गया है कि यह ज्ञान की इच्छा से इनकार कर दिया गया था कि क्या याचिकाकर्ताओं के परिवार उसमें निवास कर रहे हैं। फिर से पैरा 6 में यह दोहराया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास 17 नवंबर, 1982 को विवाद में भूमि पर कोई घर नहीं था, अर्थात, अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने की तारीख। मुआवजे के भुगतान के संबंध में, यह पैराग्राफ 13 में कहा गया था, कि भूमि का मुआवजा जल्द ही याचिकाकर्ताओं को दिया जाएगा।

(३) सुनवाई की अंतिम तिथि पर, यानी, १२ जनवरी, १ ९ of ,, लैंड एक्विजिशन कलेक्टर को एक हलफनामा दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया था कि पुरस्कार की राशि याचिकाकर्ताओं को 21 सितंबर को पुरस्कार के निर्माण के समय दी गई थी, 1986, जैसा कि अधिनियम की धारा 31 के तहत आवश्यक है या इनकार करने के मामले में, यह राशि जिला न्यायाधीश के समक्ष जमा की गई थी। उक्त आदेश के अनुसरण में, 10 फरवरी, 1988 को एक affida- vit, इस न्यायालय में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दायर किया गया था, जो कि के तहत पढ़ता है:

"कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार 8 फरवरी, 1988 को 21 सितंबर, 1986 को पुरस्कार की घोषणा के समय याचिकाकर्ताओं में से कोई भी याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं को उक्त तारीख पर मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। कहा कि राशि R.D. में या जिला न्यायाधीश के साथ जमा नहीं की गई है और अभी भी प्रतिपक्ष के कार्यालय के साथ झूठ बोल रही है। "

(४) याचिकाकर्ताओं के लिए सीखा वकील ने कहा कि चूंकि वे पहले से ही अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले प्राप्त भूमि पर पहले से ही घरों का निर्माण कर चुके हैं, इसलिए सरकार के अनुसार अधिग्रहण से मुक्त होने के लिए उत्तरदायी था। नीति। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि जिस भूमि पर घरों का निर्माण अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है, उसे अधिग्रहण से छूट दिया गया है और इसलिए, याचिकाकर्ताओं की भूमि को भी छूट देने के लिए उत्तरदायी था। किसी भी मामले में, सीखा वकील ने तर्क दिया, आज भी पुरस्कार के तहत कोई भुगतान नहीं किया गया है, और न ही राशि जिला न्यायाधीश के साथ जमा की गई है, जैसा कि अधिनियम की धारा 31 के तहत चिंतन किया गया है। पुरस्कार, यदि कोई हो, कोई परिणाम नहीं था और इसलिए, कार्यवाही को विचित्र किया जाता है।

(५) दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए सीखा वकील ने प्रस्तुत किया कि एक बार कब्जा कर लिया गया है, भूमि निहित है राज्य सरकार में और इसलिए, रिट याचिका को अकेले इस छोटे मैदान पर खारिज कर दिया गया था। इस कॉन-टेंशन के समर्थन में, इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को नरिनजान सिंह बनाम पंजाब राज्य (1) में किया गया था। सीखा वकील ने आगे कहा कि कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी कि पुरस्कार के बाद की राशि को जिला न्यायाधीश के साथ जमा किया जाना चाहिए, यदि उस समय दावेदार मौजूद नहीं थे।

(६) प्रस्ताव सुनवाई के समय, अधिग्रहित भूमि से याचिकाकर्ताओं के फैलाव को रोक दिया गया था। उत्तरदाताओं ने कभी भी उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी या जमीन पर उसी को अलग करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जो भूमि का कब्जा पहले ही ले लिया गया था। वापसी के अनुसार, 21 सितंबर, 1986 को कब्जा किया गया था। यह दिखाने के लिए कोई वृत्तचित्र सबूत नहीं दिया गया है कि उस तारीख पर कब्जा किया गया था क्योंकि उस तारीख को पुरस्कार दिया गया था। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, यह नहीं आयोजित किया जा सकता है कि अधिग्रहीत भूमि के कब्जे को उत्तरदाताओं द्वारा तब लिया गया था और इसलिए, अधिग्रहित भूमि राज्य सरकार में निहित थी।

(६ ए) यह विवादित नहीं है कि सरकार की नीति के अनुसार, जिस भूमि पर व्यक्तियों ने निर्माण उठाया है, उसे हासिल नहीं किया जाना था। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से निवेदन किया है कि उन्होंने अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले प्राप्त भूमि पर निर्माण किया है। इसके बजाय, यह रिट याचिका के पैराग्राफ 2 में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 1978 में प्यूका हाउसों को उठाया था। अब उनके संबंधित परिवारों के साथ याचिकाकर्ता इन घरों में रह रहे हैं। उत्तरदाताओं की ओर से दायर किए गए रिटर्न में, पैराग्राफ 2 में, यह कहा गया है कि 17 नवंबर, 1982 को धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के समय भूमि में कोई पक्के घर नहीं था, और यदि कोई कॉन-स्ट्रक्चर उसके बाद बनाया गया है, यह अवैध और अनधिकृत था। इसके अलावा, यह ज्ञान की इच्छा से इनकार कर दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं के परिवार उसमें निवास कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियां दायर कीं, जिसमें कहा गया था कि कीर्ति नगर की भूमि को अधिग्रहण से छूट दी गई है और वास्तव में भूमि अधिग्रहण की सिफारिशों पर- कीर्ति नगर की भूमि को छूट दी गई थी घरों के निर्माण के कारण। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने अधिग्रहित भूमि पर भी निर्माण किया है, इसलिए यह भी होने के लिए उत्तरदायी था छूट

प्राप्त। उत्तरदाताओं की ओर से दायर किए गए रिटर्न में, यह स्वीकार किया गया था कि सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने के समय सभी का निर्माण किया गया क्षेत्र अधिग्रहण से बाहर छोड़ दिया जाए। हालांकि, वापसी के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के पास 17 नवंबर, 1982 को, विवाद में जमीन पर कोई घर नहीं था। हालांकि यह तथ्य का एक विवादित प्रश्न हो सकता है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से, यह स्पष्ट है याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले प्राप्त भूमि पर निर्माण किया था।

() अधिनियम की धारा ३१, अब तक यह इन याचिकाओं के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक है, के रूप में पढ़ता है:

"31. अदालत में मुआवजे या उसी के जमा का भुगतान ।- (1) धारा 11 के तहत एक पुरस्कार देने पर, कलेक्टर पुरस्कार के अनुसार हकदार व्यक्तियों के लिए उनके द्वारा दिए गए मुआवजे का मुआवजा देने का भुगतान करेगा, और भुगतान करेगा। जब तक यह अगले उप-खंड में उल्लिखित कुछ एक या अधिक आकस्मिकताओं द्वारा रोका जाता है, तब तक यह उनके लिए।

(२) यदि वे इसे प्राप्त करने के लिए सहमति नहीं देंगे, या यदि कोई व्यक्ति भूमि को अलग करने के लिए सक्षम नहीं है, या यदि मुआवजे को प्राप्त करने के लिए शीर्षक के रूप में कोई विवाद है या इसके बारे में बताया गया है, तो कलेक्टर जमा करेगा अदालत में मुआवजे की राशि जिसमें धारा 18 के तहत एक संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा। "

10 फरवरी, 1988 को इस अदालत में दायर किए गए हलफनामे से, यह काफी स्पष्ट है कि उक्त राशि को आर.डी. में या जिला न्यायाधीश के साथ जमा नहीं किया गया था। ऐसा होने के नाते, 21 सितंबर, 1986 को पुरस्कार, याचिकाकर्ताओं के संबंध में एक वैध पुरस्कार नहीं था।

भूमि के अधिग्रहण के लिए समाप्त हो जाएगा।

(९) इन परिस्थितियों में, सभी रिट याचिकाएँ सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है। उन अधिसूचनाओं को जिनके द्वारा याचिकाकर्ताओं की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और जिन पर उन्होंने पहले से ही अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले निर्माण उठाया है, उस सीमा तक खड़े हो गए। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित

उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
जींद, हरियाणा